बैंकों में बगैर दावे के 2518 करोड़

वर्षों से लेनदेन बंद, खाते निष्क्रिय

230 करोड़ रुपयों के दावेदारों का इंतजार

> भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी भोपाल में 5 लाख 63 हजार 659 निष्क्रिय बैंक खातों में करीब 230 करोड़ रुपये जमा हैं. इनमें सरकारी बैंकों में लगभग 20 करोड़ रुपये और निजी बैंकों में 210 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है. वहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे खातों में करीब 2,518 करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं.वर्षों से लेन-देन नहीं होने के कारण यह राशि खातों में निष्क्रिय पड़ी है और बड़ी संख्या में खाताधारक या उनके वारिस अब तक इस पर दावा नहीं कर सके हैं. आरबीआई और बैंकों के प्रयास से प्रदेश में भी बड़ी संख्या में खाताधारकों और उनके वारिसों को उनकी लावारिस जमा राशि वापस मिल रही है. अनुमान है कि अब तक प्रदेश करीब 100 से 250 करोड़ रुपये तक की राशि लोगों को लौटाई जा चुकी है.

प्रांजुल पाण्डेय

भोपाल, 17 जुलाई. यदि आपका कोई पुराना बैंक खाता वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है और उसमें जमा राशि के बारे में आप भूल चुके हैं, तो अब उसे वापस पाना आसान हो गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी और दावा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उद्गम पोर्टल शुरू किया है. इसके माध्यम से ग्राहक तीन आसान चरणों में अपने नाम से जमा अनक्लेम्ड राशि की जानकारी प्राप्त कर उसे ब्याज सहित वापस हासिल कर सकते हैं. आरबीआई के अनुसार, किसी बैंक खाते में लगातार दो वर्ष तक कोई लेनदेन नहीं होने पर उसे इनऑपरेटिव खाता माना जाता है. यदि 10 वर्षों तक भी खाता निष्क्रिय रहता है, तो उसमें जमा राशि आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में स्थानांतरित कर दी जाती है. हालांकि, ग्राहक या उसका कानूनी वारिस आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी शाखा में दावा कर यह राशि वापस प्राप्त कर सकता है. उद्गम पोर्टल पर फिलहाल देश के 30 प्रमुख बैंक जुड़े हैं. ग्राहक आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म भरकर राशि का दावा कर सकते हैं. सत्यापन के बाद पात्र होने पर जमा धनराशि और नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

निगम, मंडलों के डायरी, कैलेंडर छपाने और खरीदने पर लगाई रोक

वित्त विभाग ने निगम, मंडलों से मांगा लाभांश

फिजूलखर्ची पर अब सख्ती से नकेल कसने के मूड में सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 जुलाई. राज्य सरकार अब विभागों और निगम, मंडलों सहित अन्य सरकारी उपक्रमों के फिजूलखर्ची पर सख्ती से नकेल कसने के मूड में आ गई है. राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं जिसमें बड़ी राशि नगद में खर्च की जाती है, उसके लिए पहले ही पैसों का इंतजाम करने के लिए अब वित्तीय प्रबंधन पर फोकस किया जा रहा है.

इस बीच वित्त विभाग ने निगम, मंडलों और उपक्रमों से लाभांश की मांग कर दी है. अब निगम, मंडलों के लिए ये जरुरी होगा कि वे जल्द से जल्द अपनी कमाई में सरकार के खजाने में लाभांश की राशि जमा कराएं. वित्त विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, सभी प्रबंध संचालक राज्य के सार्वजनिक उपक्रम और सभी कलेक्टरों को बाकायदा पत्र जारी किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के तहत वित्तीय प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें विभागों को खर्च में कटौती करने की नसीहत देने के साथ ही कई खर्चों पर नकेल भी कस दी है. वित्त विभाग ने शुक्रवार को जो ताजा निर्देश दिए हैं, उसमें अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर ऐसी विदेश यात्राएं जिनके फलस्वरूप राज्य शासन अथवा राज्य के निगम, मंडल, उपक्रम, विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्थाएं अंतर्गत व्यय है, उन सभी के लिए विदेश यात्राएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. यानी अब निगम, मंडल के अधिकारी और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्ययन यात्रा या फिर किसी और प्रयोजन के बहाने विदेश की यात्रा नहीं कर सकेंगे, इसी तरह विश्वविद्यालयों के कुलपति, फेकल्टी या प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे. इसी तरह वित्त विभाग ने सभी निगम, मंडलों और उपक्रमों के साथ ही अन्य संस्थाओं द्वारा नए वर्ष या अन्य मौकों पर डायरी, कैलेण्डर छापने या खरीदने के लिए चलन पर भी रोक लगा दी है. अब कोई भी सार्वजनिक उपक्रम अपनी ओर से इस तरह की कोई गतिविधियां नहीं करेंगे. सामान्य तौर पर ज्यादातर निगम, मंडल अपनी ओर से कैलेण्डर का प्रकाशन कराते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

अब होटल में नहीं होंगी कार्यशालाएं

वित्त विभाग ने निगम, मंडलों द्वारा होटल तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं आदि में कार्यशाला करने, बैठकें करने या फिर किसी भी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सख्ती से रोक लगा दी है. वित्त विभाग ने सलाह दी है कि इस तरह के कार्यक्रम के स्थान पर वर्चुअली प्रशिक्षण या फिर वेबिनार का आयोजन किया जाना चाहिए. वित्त विभाग ने ताजा निर्देश में कहा है कि अधिकारी विशिष्ट को अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने की स्थिति में अतिरिक्त कार्य वाले पद के लिए आवंटित वाहन को कार्यालयीन कार्य के लिए नियत पात्रता धारण करने वाले अन्य शासकीय अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि विभाग में संलग्न अनुबंधित वाहनों पर होने वाले व्यय में कमी हो सके.

निगम, मंडलों में आंतरिक साज सज्जा पर भी रोक

वित्त विभाग सरकारी कार्य से केवल इकोनोमी श्रेणी की हवाई यात्रा की ही मंजूरी दी है, इसके अलावा किसी अन्य क्लास जैसे प्रीमियम इकोनॉमी या फिर बिजनेस क्लास में यात्रा की अनुमति नहीं होगी. वहीं अब सरकारी कार्यालयों के आंतरिक साज-सज्जा पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यानी निगम-मंडल के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अब अपने कक्ष का नए सिरे से साज-सज्जा नहीं करा सकेंगे. कमोबेश दूसरे शासकीय कार्यालयों में भी यही नियम लागू होंगे.

दो अधिकारी करेंगे कार पुलिंग

विभागों में फिजूलखर्ची को नियंत्रित करने के लिए अब किराये के वाहनों को भी सीमित किया जाएगा. इसके लिए वाहनों को पूल किया जाएगा, विभागाध्यक्ष स्तर पर इस तरह के मामले के लिए समीक्षा की जाएगी और वाहनों के आवंटन को युक्तियुक्त किया जाएगा. दो या दो से अधिक अधिकारियों के बीच एक ही वाहन का आवंटन किया जाएगा. सबसे बड़ी बात ये कि वित्त विभाग ने सभी निगम, मंडल, उपक्रमों से लाभांश की मांग भी कर दी है.

एक नजर में

सगाई से नाराज किशोरी ने नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या

मुरैना. मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने बुधारा पुल से क्वारी और आसन नदी के संगम में छलांग लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने किशोरी की तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा. शुक्रवार सुबह अभियान दोबारा शुरू किया गया और काफी मशक्कत के बाद नदी से किशोरी का शव बरामद किया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किशोरी घर से ऑटो रिक्शा से पोरसा पहुंची और वहां से बस द्वारा बुधारा पुल गई थी.

बंद बुजुर्ग महिला को पुलिस ने मुक्त कराया

आगरमालवा. जिले के सुसनेर नगर में कथित रूप से दो माह से कमरे में बंद रखी गई एक बुजुर्ग महिला को पुलिस ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुक्त कराया. बाद में दोनों पक्षों से चर्चा के उपरांत महिला को उसके तीसरे पुत्र के साथ भेज दिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार सुसनेर के वार्ड क्रमांक-5 स्थित कल्याण जीन क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला कौशल्याबाई को उसके दो पुत्रों द्वारा कमरे में बंद रखे जाने की सूचना पड़ोसियों ने नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी और पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा को दी.

फिर सक्रिय होगा मानसून

दो जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में अब भी 13% वर्षा की कमी

भोपाल, 17 जुलाई. मध्य प्रदेश में करीब नौ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को बालाघाट और डिंडोरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि प्रदेश के 31 से अधिक जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार बालाघाट और डिंडोरी के अलावा हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, रायसेन, सागर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सिवनी, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, भिंड, दतिया, मैहर, अनूपपुर और उमरिया सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है.

वहीं, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच सहित कई क्षेत्रों में उमस और गर्मी का असर बना रह सकता है. लगातार नौ दिनों से व्यापक बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश में अब तक 243.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 281.3 मिमी होनी चाहिए थी. इस तरह मध्य प्रदेश में फिलहाल 13 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है.

> प्रदेश के 35 जिले अब भी सामान्य से कम वर्षा वाले दायरे में हैं. दूसरी ओर देवास, हरदा, इंदौर, सीहोर, भोपाल और उज्जैन जैसे जिलों में वर्षा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है. अब तक सबसे अधिक बारिश देवास में दर्ज की गई है, जहां सामान्य से 102 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है. इसके विपरीत आलीराजपुर सबसे सूखा जिला बना हुआ है, जहां सामान्य से 74 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

प्रतिमा के एससी प्रमाणपत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 जुलाई. प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाणपत्र को राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा वैध ठहराए जाने के बाद यह मामला अब न्यायालय की दहलीज तक पहुंचने जा रहा है.

शिकायतकर्ता एवं प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने समिति के निर्णय को खारिज करते हुए इसे सरकारी दबाव में लिया गया फैसला बताया और हाईकोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है. अहिरवार ने आरोप लगाया कि जांच समिति ने संविधान

(अनुसूचित जाति) आदेश-1950, वर्ष 1961 एवं 1971 की जनगणना के अभिलेख तथा वर्ष 1998-99 में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) की मानवशास्त्रीय रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी की. उनका दावा है कि उक्त रिपोर्ट में विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के बागरी समाज को अनुसूचित जाति नहीं, बल्कि राजपूत/ठाकुर समुदाय का उपसमूह बताया गया है.

संगठन की मजबूती पार्टी की बड़ी ताकत

नेताओं ने कार्यकर्ताओं से ऐतिहासिक जीत दिलाने का किया आह्वान

नवभारत न्यूज

दतिया/ग्वालियर, 17 जुलाई. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि विकसित दतिया, विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा को मजबूत करना आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता विचार और राष्ट्रसेवा की भावना से कार्य करते हैं तथा संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को

ऐतिहासिक जीत दिलाने का आह्वान किया.

शुक्रवार को होटल रतन रॉयल में भाजपा के दतिया उपचुनाव कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा, उपचुनाव प्रभारी सांसद भारत सिंह कुशवाह तथा भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और जनसंपर्क को लेकर मार्गदर्शन दिया.

दिग्विजय से मिले के के मिश्रा

आधे घंटे तक हुई बंद कमरे में चर्चा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 जुलाई. मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया विभाग अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता केके मिश्रा ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से उनके भोपाल स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट की.

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों तथा समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. आगामी विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के बीच हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है. हालांकि बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. मुलाकात के दौरान इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंदू अग्रवाल, कांग्रेस सेवादल महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारी अध्यक्ष मीनाक्षी जायसवाल, यशपाल सिंह गहलोत तथा किसान नेता अंकित जिरेटी भी मौजूद रहे.

केन-बेतवा में अनियमितताओं का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 जुलाई. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को 'द केन-बेतवा फाइल्स' जारी करते हुए 44 हजार करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाया और पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की.

उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को छतरपुर जिले के आंदोलन स्थलों के दौरे के दौरान एकत्र दस्तावेजों और प्रभावित लोगों के बयानों के आधार पर ग्राम सभा की कार्यवाही, मुआवजा वितरण, भूमि अभिलेख, पुनर्वास और पुलिस कार्रवाई में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं.

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि कई ग्राम सभाओं के अभिलेखों में एक जैसी कार्यवाही दर्ज है तथा कुछ स्थानों पर ऐसे हस्ताक्षर पाए गए हैं, जो संबंधित व्यक्ति के सरपंच बनने से पहले की तिथि के बताए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि करोड़ों रुपये का मुआवजा अपात्र लोगों को स्वीकृत किया गया, जबकि वास्तविक प्रभावित परिवारों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों को अब तक भुगतान नहीं मिला.

उन्होंने पुनर्वास में देरी, किसानों की जमीन का कथित रूप से जबरन अधिग्रहण और आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. साथ ही, परियोजना के एक बड़े बांध के ठेके को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिए गए चंदे और ठेकों के आवंटन के बीच कथित संबंधों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परियोजना में पारदर्शिता और आदिवासी अधिकारों की हर हाल में रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

दतिया बदलाव के लिए तैयार है : पटवारी

बड़ोनी, बसई एवं उदगंमा में कार्यकर्ता बैठकों के साथ संवाद कार्यक्रम

दतिया, 17 जुलाई. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज दतिया विधानसभा उपचुनाव के तहत ग्राम बड़ोनी, बसई एवं उदगंमा में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठकों एवं संवाद कार्यक्रमों में भाग लिया.

इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, उपचुनाव प्रभारी सिद्धार्थ कुशवाह एवं लाखन सिंह यादव, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे. ग्राम बड़ोनी में आयोजित कांग्रेसजन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया का उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं,

बल्कि जनता के सम्मान, विकास और जनहित की राजनीति को मजबूत करने का चुनाव है.

उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही घर-घर जाकर जनता से संपर्क करे, कांग्रेस की नीतियों और जनसरोकारों को लोगों तक पहुंचाए तथा कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को प्रचंड मतों से विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाए.

कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का चुनाव शून्य घोषित

याचिकाकर्ता की भी मांग खारिज

नव भारत न्यूज

इंदौर. शुक्रवार को जिला कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसाफ अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को पार्षद घोषित करने की मांग भी खारिज कर दी. इसके साथ नगर निगम परिषद में कांग्रेस के दो पार्षद कम हो गए और दोनों ही मुस्लिम हैं.

जिला कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने नगर निगम वार्ड 60 की पार्षद सुनहरा अंसाफ अंसारी का चुनाव शून्य घोषित करने का फैसला सुनाया. कांग्रेस पार्षद ने निर्वाचन फार्म में संपत्तिकर एवं जलकर की राशि बकाया होने की जानकारी छुपाई थी. इसको लेकर यास्मीन इखतियार मुन्ना अंसारी ने कोर्ट में वकील के माध्यम से याचिका दायर की थी. याचिका में सुनहरा का निर्वाचन शून्य करने और

यास्मीन इखतियार अंसारी को पार्षद घोषित करने की मांग भी की गई थी. आज जिला कोर्ट में जस्टिस विनोद कुमार शर्मा ने उक्त मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. जिला कोर्ट के न्यायाधीश ने निगम के वार्ड 60 की कांग्रेस पार्षद का चुनाव निर्वाचन फार्म में संपत्तिकर एवं जलकर राशि छुपाने के तथ्यों को सही माना. उसी आधार पर सुनहरा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता इखेयार मुन्ना अंसारी की पत्नी यास्मीन को पार्षद घोषित करने की मांग भी खारिज कर दी है. उक्त फैसले की सूचना कलेक्टर, निगमायुक्त और राज्य चुनाव आयोग को देने के भी आदेश दिए हैं.

चुनाव पहले रद्द किया जा चुका

ध्यान रहे कि निगम के वार्ड 58 के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का पार्षद चुनाव पहले ही रद्द किया जा चुका है. आज सुनहरा अंसाफ अंसारी का निर्वाचन शून्य होने से शहर और निगम परिषद में कांग्रेस के दो पार्षद कम हो गए हैं.

एक नजर में | सिक्स लेन बनाने वाली कंपनी रवि इंफ्रा को मिला ठेका, बोरिंग मशीन से हो रही मिट्टी की जांच, सड़क पर साइट होंगी क्लियर

जमीन के अंदर और बाहर चल रही एलिवेटेड ब्रिज की पड़ताल, 10 दिन में फाइनल होगी ड्राइंग डिजाइन

प्रमोद व्यास

उज्जैन. सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत शहर की सबसे महत्वाकांक्षी एलिवेटेड ब्रिज योजना अब जमीन पर उतरने लगी है. निर्माण एजेंसी ने एक ओर जमीन के अंदर फाउंडेशन की मजबूती परखने के लिए बोरिंग कर मिट्टी की जांच शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर जमीन के बाहर यह सर्वे किया जा रहा है कि निर्माण के लिए किन-किन हिस्सों को क्लियर करना होगा. अगले 10 दिनों में परियोजना की अंतिम डिजाइन फाइनल होने के बाद एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी.

नवभारत से चर्चा में सिंहस्थ विंग के कार्यपालन यंत्री अवनेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल आगर रोडस्थित मकोड़िया आम से चामुंडा चौराहे तक फाउंडेशन बोरिंग का काम तेजी से चल रहा है. इंजीनियर मिट्टी की क्षमता और फाउंडेशन की स्थिति का परीक्षण कर रहे हैं, ताकि एलिवेटेड ब्रिज की संरचना पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बनाई जा सके. साथ ही सड़क के दोनों ओर उन स्थानों का भी सर्वे किया जा रहा है, जहां निर्माण के लिए जगह खाली करानी होगी.

दिसंबर 2027 तक प्रोजेक्ट पूरा - योजना के तहत शहर में दो एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिन्हें दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सिंहस्थ-2028 से पहले इन्हें यातायात के लिए चालू किया जा सके. इनमें एक फ्लाईओवर फोरलेन और दूसरा टू-लेन होगा. दोनों की ऊंचाई मौजूदा सड़क से औसतन 8 मीटर से अधिक रहेगी.

पहले एलिवेटेड यहां बनेगा - पहला एलिवेटेड कॉरिडोर चिमनगंज मंडी (इंदिरानगर) चौराहे से इंदौर गेट होते हुए हरिफाटक ब्रिज तक बनाया जाएगा. इसकी लंबाई करीब 3.53 किलोमीटर होगी और यह फोरलेन रहेगा. इसके नीचे सर्विस रोड भी विकसित की जाएगी, ताकि स्थानीय यातायात प्रभावित न हो.

दूसरा ब्रिज यहां बनेगा - दूसरा एलिवेटेड ब्रिज इंदौर गेट से निकास चौराहे तक करीब 1.732 किलोमीटर लंबा होगा. यह टू-लेन कॉरिडोर रहेगा, जो पुराने शहर के घने बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के ऊपर से गुजरेगा. इसके नीचे भी सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा.

4 16 करोड़ का काम 300 में

करीब 416 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए शासन से सक्षम स्वीकृति मिल चुकी है. पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ विंग द्वारा जारी टेंडर में रवि इंफ्रा सबसे कम बोलीदाता के रूप में सामने आई है. कंपनी ने करीब 300 करोड़ रुपये में निर्माण कार्य पूरा करने की पेशकश की है. तकनीकी और वित्तीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा.

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद इंदिरानगर, चिमनगंज मंडी, इंदौर गेट, देवासगेट, चामुंडा, चरक अस्पताल, कोयला फाटक, गाड़ी अड्डा, नई सड़क, दौलतगंज और निकास क्षेत्र सहित 15 से अधिक प्रमुख चौराहों पर यातायात का दबाव कम होगा. पुराने शहर में लगने वाले रोजाना के जाम से राहत मिलेगी, यात्रा का समय घटेगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60